

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

R 277-I 12

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

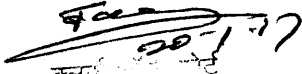
214
/2016-17

पुनरीक्षणकर्ता/
आवेदक

:-

सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड द्वारा
डारेक्टर-संजय श्रीवास्तव पिता स्व. श्री
एल.के. श्रीवास्तव, निवासी- 215, श्री
राम नगर वीरसवरकर वार्ड गढ़ा,
जबलपुर, तह. व जिला जबलपुर (म.प्र.)

द्वारा आज दि 20-1-17 को
प्रस्तुत


कलम 50 म.प्र.
राजस्व मण्डल ग्वालियर

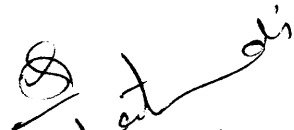
विरुद्ध

गैर-पुनरीक्षणकर्ता/
अनावेदक

:-

1. सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड
कार्पोरेट पहचान संख्या U45200 MP
2011P/PTC 025834 पता 516, बड़े जैन
मंदिर के पास गढ़ा जबलपुर, द्वारा-
प्रबंध निदेशक अयोध्या त्रिपाठी,
2. विनोद चाटे पिता स्व. मुरलीधर चाटे,
निवासी- शक्तिनगर, जबलपुर म.प्र.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959


20/1/17

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण
अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोरखपुर, जबलपुर
के समक्ष वर्तमान आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ प्रस्तुत
स्थगन आवेदन का निराकरण न किये जाने से व्यथित होकर
निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत है ।



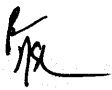
XXXIX(a)BR(H)-11

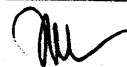
सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड विरुद्ध
सतपुड़ा इन्फ्राकॉन प्रायवेट लिमिटेड आदि
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 277-एक/17


जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-1-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के प्र०क० 21/अ-6/2016-17 में अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन/शीघ्र सुनवाई के आवेदन का निराकरण न किए जाने के विरुद्ध म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित धारा 50 के तहत पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 11-1-17 के विरुद्ध उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 21/अ-6/2016-17 दिनांक 16-1-17 को पेश की गई, जिस पर से उन्हें दिनांक 28-1-17 की तिथि दी गई । आवेदक द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिनांक 17-1-17 पेश कर स्थगन आवेदन का निराकरण किए जाने का निवेदन किया गया परंतु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं मौखिक रूप से कहा गया कि शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर भी दिनांक 28-1-17 को ही सुनवाई की जायेगी । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अनावेदक तहसीलदार के आदेश की आड़ में प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने हेतु प्रयासरत हैं और यदि भूमि का विक्रय कर दिया गया तो उन्हें अपूर्ण्य क्षति होगी तथा नये विवाद पैदा होंगे । उक्त आधार पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी ग्राह्य कर तहसीलदार के आदेश को स्थगित करने का निवेदन किया गया है ।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का</p>	





R 277 E/17
कर्यवाही तथा/आदेश

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा/आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>तथा उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । चूंकि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई है जो सुनवाई हेतु लंबित है ऐसी स्थिति में इस निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात न्यायहित में यह आदेश दिए जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर अंतिम आदेश पारित किये जाने अथवा तीन माह (जो भी पहले हो) तक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाये और उभयपक्षों द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कय-विकय/अंतरण आदि न किया जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p align="right">  सदस्य </p>

R
2/18